

### प्रतिक्रिया / अफोर्डेबल हाउसिंग के ऐलान का रियल्टी सेक्टर ने किया स्वागत, कहा 'अब तेजी से होगा काम'



- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अफोर्डेबल और मिडल इनकम हाउसिंग के लिए एक स्पेशल विंडो की घोषणा की

Moneybhaskar.Com | Sep 14, 2019 06:23:13 PM IST

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रियल्टी सेक्टर को राहत देते हुए अफोर्डेबल और मिडल इनकम हाउसिंग के लिए एक स्पेशल विंडो की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हाउसिंग परियोजना के लिए लास्ट माइल फंडिंग जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके तहत अफोर्डेबल और मिडल इनकम श्रेणी की ऐसी परियोजनाओं को फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जो न तो एनपीए हैं और न ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की प्रक्रिया से गुजर रही हों। साथ ही इनका नेटवर्थ शून्य से अधिक होना चाहिए। इसे फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का भी ऐलान किया। क्षेत्र की कंपनियों ने इस घोषणा की तारीफ की है। इसे स्वागत योग्य बताया है।

#### आइए जानते हैं किसने क्या है :

मनोज गौड़ (एमडी, गौड़ ग्रुप एंड चेयरमैन, अफोर्डेबल हाउसिंग कमिटी, क्रेडाई) ने कहा 'आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा वास्तव में स्वागत योग्य है। इससे कई मध्य-आय और किफायती आवास परियोजनाएं जो धन की कमी के कारण धीमी हो गई थी वहां अब तेजी से काम होगा।'

प्रदीप अग्रवाल (को-फाउंडर एंड चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल एंड चेयरमैन) ने कहा 'यह कदम वाकई स्वागत योग्य है। वित्त मंत्री द्वारा स्पेशल विंडो की घोषणा के बाद मध्यम आय वाले आवासों को काफी मदद मिलेगी। सरकार का सपना '2022 तक सभी के लिए आवास' का उद्देश्य पूरा होगा।'

मोहित गोयल (सीईओ, ओमेक्स लिमिटेड) ने कहा 'इस क्षेत्र के लिए त्योहारी सीजन से पहले अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्री ने परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फंड रियल्टी सेक्टर को बूस्ट करने में मदद करेगी। इन घोषणाओं के बाद घर खरीदारों के आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेज गति से काम होगा।'

धीरज जैन (डायरेक्टर, महागुन ग्रुप) का कहना है, 'यह रियल सेक्टर के लिए बड़ी राहत है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या फंडिंग की थी जिसका निवारण कर लिया गया है। अब इस सेक्टर में तेजी आएगी। उम्मीद है कि फैसले से अधूरे मकान पूरे होंगे। सरकार के इस समर्थन से बाजार और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और कई खरीदारों को जल्द ही अपने घरों का कब्जा मिल जाएगा। हम ऐसे निर्णय लेने के लिए एफएम का स्वागत करते हैं जो कि लाखों खरीदार लाभान्वित होंगे।'

'हम वास्तव में आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित हाल के कदमों की सराहना करते हैं और खुश हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर द्वारा लंबे समय से मांग किए गए इन प्रावधानों को आखिरकार कागज पर लाया गया है।' यह अमित मोदी (डायरेक्टर एबीए कॉर्प एवं क्रेडाई के वेस्टर्न यूपी से प्रेसिडेंट) का कहना है।